श्री रवि राय : लेकिन आपने लाइसेंस क्यों दिया ?

SHRI TULSIDAS JADHAV : Looking at the statement which gives particulars of assistance given by the LIC, I find that 64.29 per cent of the funds of the LIC are invested in the group of ten industrialists. I want to know why so much of money has been given only to ten such groups. Are there no small industrialists asking for loan from the LIC ?

SHRI F. A. AHMED : In the past, LIC was not giving loans to the small scale industries. It was investing its money only in the larger business houses with a view to getting more profits which could be passed on to the policyholders.

श्री शशि रंजन : अध्यक्ष जी, इस सरकार के खाने के दाँत और दिखाने के दांत और हैं। एक तरफ मोनोपली को हटाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों को कर्ज देते हैं और वह कर्ज की रकम भी बढ़ती चली जा रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अब जो नया लाइसेंस देंगे क्या उस लाइसेंस में यह शर्त रखना चाहेंगे कि तुम को किसी भी रूप में कोई कर्ज नहीं दिया जायगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इन्हीं हालात की वजह से बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया है। अब जो लोन दिया जायगा उस में देखा जायगा कि किस मिकदार में हो और किस हद तक दिया जाय।

श्री शशि रंजन: इस को कम करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : बैंकों का नेशनलाइजेशन बहुत बड़ा कदम है।

SHRI HEM BARUA : In view of the fact that the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act could provide only for the future, may I know what steps the Government have taken or propose to take to attack the 75 houses of monopolists operating in this country ?

SHRI F. A. AHMED : So far as the Monopolies and the Restrictive Trade Practices Act is concerned, it is not only for the future. It will go into the facts and figures of the existing monopoly houses and necessary action will be taken against them.

SHRI BEDABRATA BARUA : When the Dutt Commission laid down Rs. 25 lakhs as the limit for licences, it was not because it was a small amount or big amount ; the idea was to have control over the big business houses and prevent them from entering any sector of industries. A fortnight ago there was a notification preventing big business houses from entering an industry with an investment of more than Rs. 5 crores. May I know what measures have been taken to prevent business houses from having binami transactions ?

SHRI F. A. AHMED : As far as possible, we shall try to prevent them.

Production of Iron and Steel

\+

*574. SHRI BENI SHANKER SHARMA :
SHRI N. R. DEOGHARE :

Will the Minister of STEEL AND HEAVY ENGINEERING be pleased to state ;

(a) the total production of Iron & Steel in the country during the last three years both in the public and Private sectors ;

(b) the total demand of Iron and Steel in the country as at present ;

(c) how far the industry is able to meet the same ; and

(d) the effect of decontrol of price on the industry ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI K. C. PANT): (a) A statement-I is laid on the Table of the House.

(b) The Steering Group has estimated the demostic demand for Mild Steel at 5.0 million tonnes in 1969-70.

(c) The industry is not able to meet the full demand. Imports made during the last three years are indicated in the statement-II laid on the Table of the House.

(d) Price of steel sold by the main producers continues to be informally controlled through the Joint Plant Committee.

Statement I

Production of Iron & Steel

(In '000 tonnes)

	1966-67		1967-68		1968-69		1969-70*	
	Pig Iron	Saleable Steel	Pig Iron	Saleable Steel	Pig Iron	Saleable Steel	Pig Iron	Saleable Steel
Public Sector	174.9	2451.9	997.3	2488.7	1121.7	2685.1	955.7	2289.5
Private Sector	810.2	2620.9	197.7	2147.0	206.9	2121.6	119.4	1669.2
	985.1	5072.8	1195.0	4635.7	1328.6	4806.7	1075.1	3958.1

Statement-II

Imports of Iron & Steel**

	Quantity (In '000 tonnes)	Value (In '000 Rs.)
1966-67	337.4	444,817
1967-68	400.3	555,787
1968-69	345.7	455,153
1969-70†	154.9	214,148

श्री बेणी शंकर शर्मा : माननीय मंत्री जी ने जो विवरण सभा पटल पर रखा है उसको देखने से मालूम होता है कि 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में प्राइवेट सैक्टर में पिग-आयरन का उत्पादन कम होता गया है। साथ ही साथ दूसरी तरह का जो लोहा है उसका उत्पादन भी उतना नहीं बढ़ा है। पब्लिक सैक्टर में जरूर पिग-आयरन का उत्पादन कुछ बढ़ रहा है, किन्तु दूसरे लोहे का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। पब्लिक सैक्टर में जरूर पिग-आयरन का उत्पादन कुछ बढ़ रहा है। किन्तु दूसरे लोहे का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर में उनकी जितनी कैपेसिटी है, उसका उपयोग इन वर्षों में किया गया है या नहीं ? यदि नही किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन वर्षों में लोहे के दामों में क्रमशः बढ़ोत्तरी हुई है या उनके दाम घटे हैं ? यदि बढ़े हैं तो कितने बढ़े हैं और घटे हैं तो कितने घटे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक पिग-आयरन के उत्पादन के घटने और बढ़ने की बात है, आम तौर पर यह होता है कि अगर इस्पात का

*April 1969 to January 1970 (both months inclusive)
**Excludes high carbon steel and alloy steel.

†April '69 to September '69.

उत्पादन बढ़ाना हो तो पहले ब्लास्ट-फर्नेस लगा लेते हैं, जिससे पिग-आयरन का उत्पादन इस्पात के उत्पादन से पहले प्राप्त हो जाता है, फिर बाकी का प्लांट लगाते हैं, जिससे उस पिग-आयरन को इस्पात में परिवर्तित किया जाता है इसलिए कुछ तो इसका यही कारण है और कुछ पब्लिक सैक्टर में पिग-आयर बनाने के लिए क्षमता छोड़ी गई है।

जहां तक कैपेसिटी के यूटिलाइजेशन का प्रश्न है—यूटिलाइजेशन पूरी रेटेड-कैपेसिटी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ यूनिटस में अच्छा है और कुछ में अच्छा नही है। दुर्गापुर में रेटेड कैपेसिटी से उत्पादन करीब-करीब आधा है। 1.6 मिलियन टन्ज की रेटेड कैपेसिटी है, लेकिन अभी वह पूरी तरह से अवेलेबिल नहीं है, इसलिए आधा है। जहां तक भिलाई का प्रश्न है, इस वक्त के आंकड़ों के अनुसार उसमें प्रोडक्शन की रफ्तार 2.2 मिलियन टन है, जब कि उसकी रेटेड कैपेसिटी 2.5 मिलियन टन है। रूरकेला में इस वक्त 1.3 मिलियन टन की रफ्तार चल रही है, जबकि उसकी कैपेसिटी 1 8 मिलियन टन है। टिसको में 1.9 मिलियन टन और इस्को में 0.8 मिलियन टन की प्रोडक्शन की रफ्तार चल रही है।

अब जहां तक दाम के घटने और बढ़ने का प्रश्न है —डी-कन्ट्रोल के साथ दाम बढ़े हैं। 1 मई 1967 को डी-कन्ट्रोल हुआ था, उस के बाद एक बार 53 रु० बढ़े, दूसरी बार 3 रुपये और तीसरी बार 57 रुपये और अभी हाल में 77 रुपये 8 आने दाम बढ़े हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ओपन-मार्केट में प्राइस इससे ऊंची है, खास तौर से उन कैटेगरीज आफ स्टील की जिनकी कमी है।

श्री वेणी शंकर शर्मा : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि खुले-बाजार में कई तरह के लोहे के दाम बहुत बढ़े हैं। मैं भी इस बात को जानता हूं—जैसे प्लेटस में हजार पन्द्रह सौ रुपये का ब्लैक है, फिर भी कम्ज्यूमर्स को उन दाम पर नही मिलता है। इस ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि बोकारों में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ? अभी हाल में माननीय मंत्री जी ने शायद राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि बोकरों में जब स्टील की पैदावार होगी उस समय उस का उत्पादन मूल्य 2725 रु० प्रति टन होगा। क्या मंत्री जी यह समझते हैं कि लोहे के जो दूसरे कारखाने हैं, उन में भी इस्पात की लागत उतनी ही है, जितनी बोकारों में होगी, यदि बोकारों की लागत ज्यादा है तो उसका क्या कारण है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि बोकारों में जो मशीनरी अभी रूस से लाई गई है, उसके बारे में बहुत से सर्कल्ज में यह कहा जा रहा है और हमारे इन्जीनियरों ने भी कहा है कि वह मशीनरी बहुत पुराने ढंग की है। क्या आपने इस बात की जांच की है कि वह नई मशीनरी है या रूस पुरानी मशीनरी को वहां डम्प कर रहा है ?

श्री कृष्ण चंद्र पन्त : माननीय सदस्य का पहला प्रश्न प्लेट्स के सम्बन्ध में था। उस को ब्लेक मार्केट कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल नहीं है। इन्फार्मेल कंट्रोल है जो कि प्रोडयूसर्स पर लागू है, लेकिन इस वक्त कोई प्रोडयूसर के बाद कंट्रोल नहीं है। इस लिए ब्लेक मार्केट कहना सही नहीं होगा, लेकिन यह सही है कि जो जे० पे०सी० की प्राइसेज प्रोड्यूसर्स पर लागू हैं उन से वह कहीं ज्यादा हैं। अब सवाल यह है कि इस को कैसे रोका जाय। इस के दो ही तरीके हैं। उत्पादन बढ़ाया जाय देश में और अगर विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो तो जितनी आवश्यकता हो उतना आयात किया जाय। यह दोनों चीजें की जा रही हैं।

जहां तक बोखारो का प्रश्न है, आप ने पूछा कि कब तक यह चलेगा । तो पहली ब्लास्ट फर्नेस के दिसम्बर, 1971 में तैयार होने का अनुमान है और मार्च, 1973 तक पहली स्टेज यानी 1.7 मिलियन टन होने का अनुमान है । फिर यह पूछा गया कि लागत क्यों अधिक दी गई, तो जब माननीय सदस्य ने इतनी तकलीफ की है कि राज्य सभा के सवाल को पढ़ा है तब फिर उस में इस का उत्तर भी दिया गया है कि लागत क्यों बढ़ी है । वह उस को भी उस में देख लें ।

श्री बेणी शंकर शर्मा : मेरा प्रश्न यह था कि रशिया जो मशीनरी भेज रहा है वह नई है या पुरानी क्योंकि हमारे इन्जीनियरों ने बतलाया है कि पुरानी मशीनरी को रंग और पालिश कर नया कह कर दिया जा रहा है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे तो कोई जानकारी नहीं है । मैं तो समझता हूं कि वह नई होगी ।

SHRI MURASOLI MARAN : Even though there is an increase of demand for steel for a long time at least for the past 15 years, this Government due to indecision and procrastination has refused to give clearance for steel plants in South India The Planning Commission has given a green signal and has now allotted about Rs. 115 crores for the proposed steel plant at Salem and other places. When are you going to announce your decision ? What is the reason for your delay ? For whose arrival are you waiting now ? The impression is created that you are all men of straw and you are waiting for a man of steel to come here. I want you dispel that doubt. I want to have a categorical reply from the Minister. When are you going to announce your decision regarding Salem steel plant ?

SHRI K.C. PANT : This matter is under study.

AN HON MEMBER : How long ?

SHRI K.C. PANT ; When it has been studied properly and we are prepared to make an announcement on the basis of the study, we shall make the announcement.

श्री द्वा०ना० तिवारी: मंत्री जी ने जो जवाब दिया वह ठीक नहीं है । प्राइसेंज ओपन मार्केट में अधिक है और जो प्रोड्यूसर्स हैं उन के दाम कम हैं । जब वह बाजार में बिकने जाता है तब दाम अधिक हो जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि जब ऐसी स्थिति है और चीज की कमी है और कंज्यूमर को प्राइसेज अधिक देनी पड़ती हैं, जो कि न गवर्नमेंट को जाता है और न प्रोड्यूसर के पास जाता है, मिडल मैन ले लेता है, तब उस को डिकंट्रोल करने की क्या जरूरत पड़ी थी । क्यों न पुनः कंट्रोल लागू करें जिससे कंज्यूमर को ठीक दाम पर मिल सके ।

दूसरा प्रश्न यह है कि पब्लिक सैक्टर को यहां बहुत बुरा भला कहा जाता है, लेकिन जो स्टेटमेंट सभा पटल पर रक्खा गया है उस में कहा गया है कि न केवल पिग आयरन का बल्कि सेलेबल स्टील का प्रोडक्शन भी प्राइवेट सैक्टर में घटता जाता है और जितनी उन क्षमता है उससे कम पिग आयरन और सेलेबल स्टील का उत्पादन हो रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे लोग जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं ताकि देश में इसका कहत रहे और अधिक दाम मिलें ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : भले ही यह दाम बढ़े हों जैसा मैंने कहा, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि सारी चीजों के दाम ओपन मार्केट में बढ़े हैं और कंज्यूमर्स को उसी दाम पर मिलता है । जो स्केअर्स कटेगरीज हैं, जिन की कमी है, उन पर इन्फार्मेल कंट्रोल है । 90 फी सदी स्केअर्स कटेगरीज प्रापर्टी सैक्टर को दी जाती हैं निर्धारित दामों पर केवल 10 फी सदी स्टाक यार्ड वगैरह को दिया जाता है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी: पब्लिक से ज्यादा दाम लिया जाता है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : उस में भी पब्लिक आता है। मान लीजिये प्राइवेट सैक्टर कोई डिफेन्स की चीज बनाता है या कुछ एक्सपोर्ट करता हो तो उस को निर्धारित दामों पर दिया जाता है प्रायारिटी से। बाहर जो आता है उसे ज्यादा दामों पर लेना पड़ता है, लेकिन उस में ऐचुअल यूजर्स के लिये स्टाक यार्ड से डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज के सर्टिफिकेट पर लेने का प्रावधान रक्खा गया है।

जहां तक दूसरा सवाल है, कुछ दिक्कतें थीं और वह दिक्कतें आप को मालूम हैं। पिछले महीने बंगाल में जो स्थिति थी उस से उत्पादन पर असर पड़ा। टिस्को में चूंकि कोक ओवन का रिपेअर करना पड़ा पिछले वर्ष, उस से भी उत्पादन पर असर पड़ा होगा।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU: Is it a fact that due to the inefficiency of the public sector steel projects, shortage of steel is being experienced by our country? Is it a fact that from 6 million tonnes of steel production in previous years it has come down to 4 million tonnes this year? Is it a fact that in Japan the capacity of one man is 150 tons; in India it is only 60 tons or 70 tons. In Durgapur Steel plant it is 47 tons. Why is there difference in production in respect of Durgapur factory compared to the other two factories? May I know what steps the Government propose to take to bring the production in line with the production as per Japanese manpower? If the Government is taking steps to bring it to the level of Japanese production, will the Goverument invite Japanese experts to advise us in respect of these three projects so that they may come up to the level of production of the Japanese manpower?

SHRI K. C. PANT: We have to take into account the practice in our own country to determine the optimum level of manpower in a steel plant. We cannot go the whole hog by either the Japanese experience or the experience of others. With regard to the second question what the hon Member has to bear in mind is this. If you want to reduce today the strength of the manpower in any of the steel plants it has to be negotiated with the trade unions. Nobody can do it unilaterally and that is not an easy proposition at all. You will appreciate, unless it is done with the cooperation of the trade unions, this cannot be done.

SHRI PILOO MODY: The Minister has made a damaging statement saying that he was not aware if the Bokaro plant was a used plant manufactured there or a new one. I want to know this from the hon Minister, whether he will find out as to what part of the Bokaro steel plant was a re-plant from the Soviet Union in India and whether he will come back to this House with a proper reply.

SHRI K. C. PANT: Sir, according to the information with me there is no reason for me to enquire into this matter. If there is any basis or any ground due to which I have to make an enquiry I shall do so.

SHRI PILOO MODY: The basis is my question.

SHRI K C. PANT: Shere is no basis.

श्री नाथूराम अहिरवार : जब से स्टील पर डिकंट्रोल हुआ है उसकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं इसलिये किसान को खेती के काम के लिए औजारों के वास्ते स्टील की जो जरूरत पड़ती है उसके लिए ज्यादा दाम देने पड़ते हैं, साथ ही एग्रीकल्चर प्राइस कमिशन ने किसान के गल्ले की प्राइस बहुत कम रक्खी है। इसको मद्देनजन रखते हुए क्या सरकार खेती के काम आने वाले औजारों के स्टील के भावों पर बन्दिश लगायेगी या इस की प्राइस पर कंट्रोल करने का विचार कर रही है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : स्टील का कैसे डिस्ट्रिब्यूशन हो इस पर अवश्य पुनर्विचार किया जायेगा।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : आनरेबल मिनिस्टर ने जो फिगर्स दिये हैं जवाब में उनके मुताबिक 1966-67 में प्रोडक्शन 5072.8 था।

[آنریبل منسٹر نے جو فیگرس دئے ہیں -
جواب میں ان کے مطابق 67-1966 میں
پروڈکشن 8.72.5 تھا]

1967-68 में 35.7
1968-69 में 48.87
1969-70 में 34.58

यह जो प्रोडकशन रहा है यह लगातार घटता रहता है । 1966-67 के मुकादले में । इस का कारण क्या है । क्या मैं सजेस्ट करूं कारण ? लेवर अनरेस्ट है, मशीन है, या कारण कैपिटल है ? प्रोडकशन बजाए बढ़ने के घटती जा रही है और क्या यही कारण नहीं है कि स्टील की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं ?

35.7 میں 1967 - 68]
48.87 میں 1968 - 69
34.58 میں 1969 - 70
یہ جو پروڈکشن رہا ہے، یہ لگاتار گھٹتا رہا ہے
67-1966 کے مقابلہ میں اس کا کارن کیا ہے۔
کیا میں سجیسٹ کروں۔ کارن۔ لیبر۔ انو ریسٹ
ہے۔ مشین ہے۔ پروڈکشن بجائے بڑھنے کے
گھٹتی جا رہی ہے اور کیا یہی کارن نہیں ہے
کہ سٹیل کی قیمتیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں۔

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रोडकशन लगातार तो नहीं घटा है लेकिन 1966-67 के मुकाबले में 1967-68 में घटा है लेकिन 1968-69 में बढ़ा है......

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : 1966-67 से घटा है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लगातार नहीं घटा है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मंत्री महोदय को ला मिनिस्ट्री में होना चाहिये था यहां नहीं ।

श्री बख्शी गुलाम मुहम्मद : मैं लगातार लफ्ज को वापिस लेता हूं ।

میں لگاتار لفظ کو واپس لیتا ہوں۔

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : 1969-70 का जहां तक ताल्लुक है ये आंकड़े अप्रेल 1969 से जनवरी 1970 तक के हैं, पूरे साल के नहीं हैं । जहां तक कारणों का सवाल है कैप्टिल के अलावा दो कारण तो हैं जो आपने बताये हैं ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Construction of Second Bridge over the Hooghly in Calcutta

*541. SHRI HIMATSINGKA : Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state :

(a) whether the proposal for the construction of a second bridge over the river Hooghly in Calcutta has made any progress ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : (a) Yes, Sir. The Government of West Bengal, who are primarily concerned with the proposed bridge, have recently set up a Hooghly River Bridge Commissioners for commencing execution of the work.

(b) Does not arise.

Boundary Disputes between States

*542. SHRI JAI SINGH :
SHRI HARDAYAL DEVGUN :
SHRI YAJNA DATT SHARMA :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the number of boundary disputes outstanding as at present between the various States of the Union ;